बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 98

डिजिटल टैक्स पर सहमति

फुकोउका में आयोजित जी-20 शिखर बैठक में डिजिटल बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कर लगाने को लेकर बनी आम सहमति से यह आशा बंधी है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के कामकाज में आमूलचूल बदलाव आएगा। इसकी बारीकियां विशद अध्ययन से सामने आएंगी लेकिन सैद्धांतिक तौर पर इस समझौते को एक सामान्य कराधान व्यवस्था के रूप में समझा जा सकता है जो तमाम जगहों पर स्वीकार्य है। इतना ही नहीं अमेरिका, जहां दुनिया की तमाम प्रमुख डिजिटल कंपनियां हैं, इस नए प्रस्ताव के खिलाफ है। जबकि ब्रिटेन और फ्रांस समेत तमाम देश इसके समर्थक हैं। उस लिहाज से देखें तो साझा डिजिटल कर संहिता लागू करने के लिए 2020 की प्रस्तावित समय सीमा हकीकत से दूर हो सकती है। बहरहाल, आगे देखें तो यह सहमति इस बात की द्योतक हो सकती है कि बड़े बहुराष्ट्रीय ऑनलाइन कारोबारों में कर व्यापकता में इजाफा हो। इससे ऐसी कंपनियों को आकर्षित करने में कर बचाने के लिए अनुकूल छोटे देशों की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त भी सीमित होगी।

वैश्विक डिजिटल कंपनियां मसलन गूगल, फेसबुक, एमेजॉन, ऐपल और तमाम अन्य को आलोचना का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि वे कम कर दर वाले देशों में मुनाफा दिखाकर अपना कर घटाती थीं। भले ही अंतिम उपभोक्ता किसी भी देश में हो। ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। ये कंपनियां एक प्रकार से कर वंचना का सहारा ले रही थीं। वे अपने क्षेत्रीय मुख्यालय को आयरलैंड, बोत्सवाना और लक्जमबर्ग जैसे देशों में स्थानांतरित करतीं जहां कर दरें कम हैं। परिणामस्वरूप अन्य देशों में कारोबार से राजस्व के मोर्चे पर अर्जित लाभ पर कम दर पर कर लगता। जी-20 का प्रस्ताव ऐसे मुनाफे पर एक साझा न्यूनतम कर लागू कर सकता है। या फिर यह ऐसी अंतरराष्ट्रीय सहमति बना सकता है कि ऐसे मुनाफे पर उन स्थानों पर कर लगेगा जहां वास्तविक राजस्व प्राप्ति हुई है। भले ही कंपनी वहां मौजूद हो या नहीं। एक और विकल्प यह है कि समझौते के तहत एक देश में पंजीकृत मुनाफे को उन देशों में पुनर्आवंटित किया जाए जहां मुनाफा हुआ हो।

इस सहमति को व्यावहारिक बनाने में कुछ बाधाएं भी हैं। पहली बात तो यह कि डिजिटल कंपनी की कोई स्वीकार्य परिभाषा नहीं है। कई मामलों में कंपनियों के पास अलग-अलग क्षेत्रों के विविध राजस्व माध्यम हैं। उदाहरण के लिए हो सकता है कंपनी भौतिक वस्तुओं की बिक्री कर रही हो जो आयातित भी हो सकती हैं। ऐसी कंपनी क्लाउड होस्टिंग सेवा भी दे सकती है और कई देशों में सर्वर भी चला सकती है। संभव है वह विज्ञापन राजस्व एक देश से जुटाए जबकि कार्यक्रम प्रसारण दूसरे देश में करे। वह विभिन्न देशों की सीमाओं से परे फिनटेक सेवाएं भी चला सकती है। ये बातें डिजिटल की परिभाषा को जटिल बनाती हैं।

तमाम सीमाओं से परे कर के उचित आकलन के लिए और कंपनियों की करवंचना या अधिकारियों के दोहरे कराधान से बचने के लिए राष्ट्रीय कर अधिकारियों के बीच उच्चस्तरीय सहयोग की आवश्यकता होगी। भारत, चीन और रूस समेत तमाम देशों की यह मांग भी इसे जटिल बनाती है कि उनके यहां संग्रहीत डेटा उनकी सीमा के भीतर ही रहे। यह मुद्दा बातचीत में गतिरोध ला सकता है।

जमीनी बाधाओं के बावजूद, जी-20 का यह प्रस्ताव डिजिटल कारोबार के भविष्य को लेकर दुनिया के रुख में अहम बदलाव को प्रस्तुत करता है। इसका असर आगे चलकर कर संहिताओं में बदलाव के रूप में भी दिखना चाहिए। यह भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे बड़े बाजारों के अनुकूल होगा बजाय कि बोत्सवाना जैसे छोटे टैक्स हैवन देशों के। यह बेहतर विकल्प नजर आता है: जिस देश में राजस्व अर्जित हो, अर्जित मुनाफे पर कर में उसकी भूमिका होनी ही चाहिए।

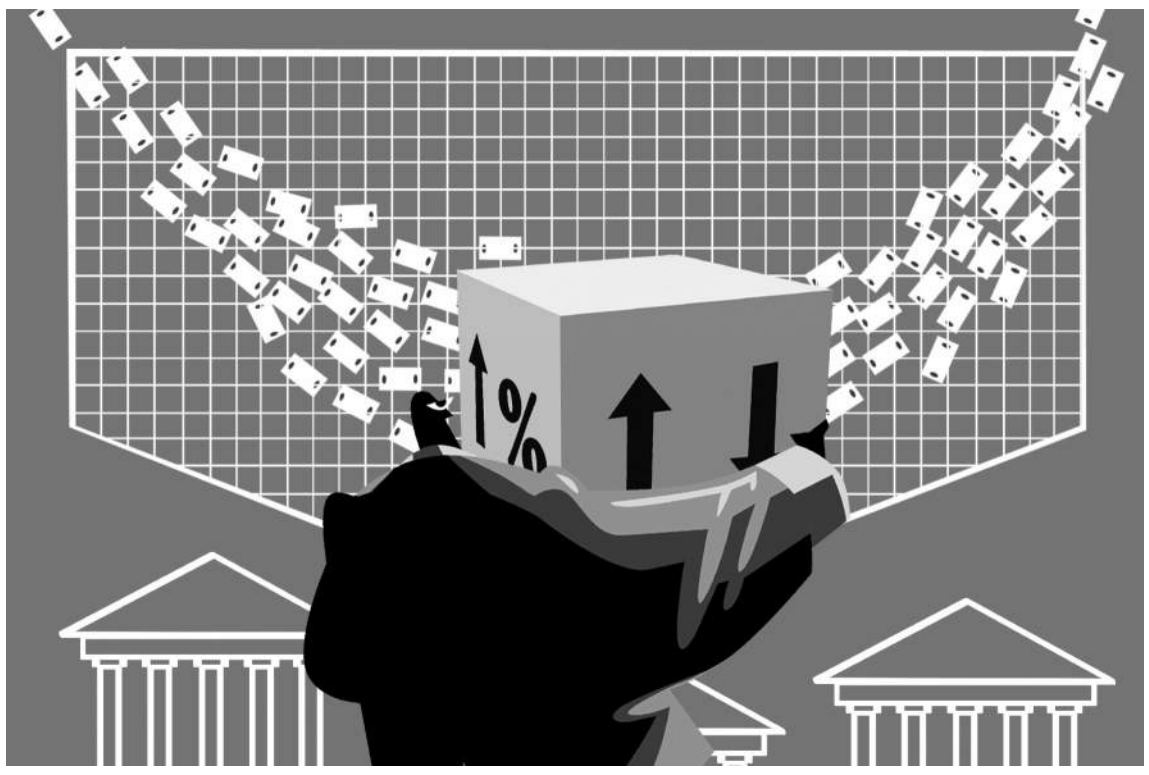

विनय सिन्हा

बाजार और ज्यादा की नहीं कर सकते थे उम्मीद

दर में कटौती, मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव व अर्थव्यवस्था में 'पर्याप्त' नकदी सुनिश्चित करने की आरबीआई की प्रतिबद्धता से बैंकों को ऋण दरें घटाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। बता रहे हैं **तमाल बंद्योपाध्याय**

एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंक ने नीतिगत दरों में 25 आधार अंक की कटौती की घोषणा कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने लगातार तीसरी बार कटौती की है। केंद्रीय बैंक ने मौद्रिक नीति का रुख भी तटस्थ से नरम कर दिया है। दर में कटौती से भी अहम पहलू नीतिगत रुख में बदलाव है। केंद्रीय बैंक ने फरवरी में अपना रुख 'सख्त' से 'तटस्थ' किया था और वर्तमान चक्र में पहली बार दर घटाई थी।

सैद्धांतिक रूप से तटस्थ रुख का मतलब है कि नीति की दिशा कोई भी हो सकती है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद मीडिया से जो कुछ कहा, उससे यह संकेत मिलता है कि अभी दरों में बढ़ोतरी की कोई संभावना नहीं है। और दरों में और कटौती हो सकती है। यह कटौती चालू वित्त वर्ष में अनुमानित राजकोषीय घाटे और मॉनसून पर निर्भर करेगी। हमें अनुमानित राजकोषीय घाटे का पता 5 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश किए जाने पर चलेगा। मॉनसून की चाल को देखना इसलिए अहम होगा क्योंकि इसका महंगाई पर असर पड़ता है।

एक अन्य पहलू गवर्नर का यह बयान है कि आरबीआई सभी उत्पादक कार्यों के लिए आर्थिक तंत्र में पर्याप्त नकदी सुनिश्चित करेगा। हाल के वर्षों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि केंद्रीय बैंक ने आर्थिक तंत्र में 'पर्याप्त नकदी' सुनिश्चित करने का वादा किया है। आरबीआई पहले की नीतियों में आर्थिक तंत्र में नकदी डालने के उपायों का जिक्र करता था। ये उपाय तथाकथित खुले बाजार की खरीद प्रक्रियाओं (ओएमओ) के तहत बाजार से सरकारी बॉन्डों की खरीद, लंबी अवधि की परिवर्तनशील-दर रीपो नीलामी, विदेशी मुद्रा खरीद/बिक्री लेनदेन और तथाकथित नकदी कवरेज अनुपात नियम आदि हैं। लेकिन ये उपाय इतनी स्पष्टता के साथ आगे की दिशा नहीं बताते थे।

पर्याप्त नकदी सुनिश्चित करने की घोषणा से बहुत लोगों की चिंताएं दूर होंगी और मौद्रिक नीति के लाभ को ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। जून के प्रारंभ में आर्थिक तंत्र में नकदी का दैनिक औसत स्तर अधिशेष हो गया, जो अप्रैल और मई में सरकार के सीमित खर्च के कारण कम था।

आरबीआई की नीतिगत दर घटकर 5.75 फीसदी पर आ गई है। इससे पहले यह इस स्तर पर जुलाई, 2010 में थी। उस समय केंद्रीय बैंक नीतिगत दर में कटौती कर रहा था और आर्थिक तंत्र में नकदी झोंक रहा था ताकि मंदी के असर से बचा जा सके। अमेरिका के जाने-माने निवेश बैंक लीमन ब्रदर्स होल्डिंग आईएनसी के दिवालिया होने के बाद मंदी ने विश्व के एक बड़े हिस्से को अपने आगोश में ले लिया था। हमने दरों में अब जैसी लगातार कटौती हाल के वर्षों में जनवरी-जुलाई, 2015 और जनवरी-जून, 2013 में देखी है। जनवरी-जुलाई, 2015 में गवर्नर रघुराम राजन ने दर 8 फीसदी से घटाकर 7.25 फीसदी की थी। वहीं जनवरी-जून, 2013 में डी सुब्बाराव ने भी दर 8 फीसदी से घटाकर 7.25 फीसदी की थी।

सुब्बाराव ने यह कदम आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए उठाया था, जो मार्च 2013 में समाप्त वित्त वर्ष में घटकर अनुमानित 5 फीसदी के स्तर पर आ गई थी। यह एक दशक में सबसे कम वृद्धि दर थी। हालांकि उस समय जब आरबीआई ने मौद्रिक नीति का रुख नरम किया तो सुब्बाराव ने दरों में कटौती की और उम्मीदों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। उन्होंने चेताया कि महंगाई में बढ़ोतरी के जोखिम से 'आगे और मौद्रिक नरमी की मामूली गुंजाइश' बची है।

वर्ष 2015 में दरों में कटौती का फैसला नीतिगत फैसलों से बाहर लिया गया था। निस्संदेह इस समय ब्याज दर का फैसला मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ले रही है, लेकिन बीते वर्षों में दोनों मौकों पर गवर्नर ने ब्याज दर में कटौती के फैसले लिए थे।

सबसे अहम बात यह है कि फरवरी और अप्रैल में दर कटौती के दौरान एमपीसी के सभी सदस्यों की आम सहमति नहीं थी। लेकिन जून की कटौती के फैसले में सभी की सहमति रही है। एमपीसी का कोई भी सदस्य दर कटौती के खिलाफ नहीं था। इसके अलावा सभी छह सदस्य नीतिगत रुख में बदलाव के भी पक्ष में रहे हैं।

इससे यह धारणा मजबूत होती है कि अगर राजकोषीय घाटा और महंगाई नियंत्रण में रहते हैं तो इस साल दरों में और कटौती की जा सकती हैं ताकि देश की वृद्धि को रफ्तार दी जा सके। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2020 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का अपना अनुमान 20 आधार अंक घटाकर 7 फीसदी कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने अपना महंगाई का अनुमान भी घटाया है। खुदरा महंगाई अप्रैल में मामूली बढ़ोतरी के साथ 2.9 फीसदी रही है, लेकिन कथाकथित कोर या गैर-खाद्य, गैर-तेल विनिर्माण महंगाई तेजी से घटी है। यह मानते हुए कि मॉनसून सामान्य रहेगा, खुदरा महंगाई 2020 की दूसरी छमाही में 3.4 से 3.7 फीसदी अनुमानित है। यह पहले के अनुमान 3.5 से 3.8 फीसदी से मामूली कम है।

भारत ने मार्च तिमाही में विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का तमगा गंवा दिया। अब चीन ने यह तमगा हासिल कर लिया है। मार्च में समाप्त वित्त वर्ष 2019 की अंतिम तिमाही में आर्थिक वृद्धि घटकर 5.8 फीसदी रही, जो पिछली 20 तिमाहियों में सबसे कम है। इससे भारत की जीडीपी की सालाना वृद्धि भी घटकर 6.8 फीसदी पर आ गई। यह मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में सबसे कम है।

फरवरी से अब तक नीतिगत दरों में 50 आधार अंकों की कटौती की गई है, लेकिन बैंकों ने अपने ग्राहकों को इसका केवल 21 फीसदी ही लाभ दिया है। बैंकों के ग्राहकों को पूरा लाभ पहुंचाने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन आर्थिक तंत्र में पर्याप्त नकदी सुनिश्चित करने और रुख में बदलाव की इस नीति से मौद्रिक लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के मुद्दे को हल करने की दिशा में प्रयास किया गया है।

जब हम आरबीआई की नकदी प्रबंधन रणनीति पर कोई ठोस खाका बना लेंगे तो दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों तक जल्द पहुंचा पाना संभव होगा। आरबीआई ने नकदी प्रबंधन ढांचे की समीक्षा के लिए एक आंतरिक समिति बनाई है। इससे पहले ऐसी समीक्षा 2014 में हुई थी।

यह समिति अपनी रिपोर्ट जुलाई के मध्य में सौंपेगी। इसे वर्तमान नकदी प्रबंधन ढांचे को आसान बनाने, लक्ष्यों में स्पष्टता लाने और केंद्रीय बैंक द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उपायों और नकदी टूलों के बारे में उपाय सुझाने हैं। आरबीआई की गुरुवार की घोषणा उम्मीदों के मुताबिक है। बाजार इससे अधिक उम्मीद नहीं कर सकते थे।

(लेखक बिज़नेस स्टैंडर्ड के सलाहकार संपादक, लेखक और जन स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड में वरिष्ठ सलाहकार हैं।)

भारतीय कंपनियों का भी 'खान मार्केट गैंग'!

इंसानी पहलू

श्यामल मजूमदार

पिछले कुछ दिनों से 'खान मार्केट गैंग' चर्चा में है। यह समाचार-पत्रों के शीर्षकों, सोशल मीडिया और लगभग हर भारतीय की सामान्य बातचीत में मौजूद है। निस्संदेह तथाकथित उदारवादी खुद के सुर्खियों में आने से खुश नहीं हैं। नरेंद्र मोदी सरकार की प्रचंड जीत से इन स्व-घोषित बुद्धिजीवियों के लगभग बेरोजगार होने का खतरा है। ऐसे में उन्हें ऐसे शांत कोने की जरूरत है, जहां वे बैठकर अपने दुखों को भुला सकें। सत्तारूढ़ सरकार इस गैंग को ताकतवर वंशवादी अमीर अल्पसंख्यकों के रूप में देखती है, जो सत्ता के सभी केंद्रों और अभिव्यक्ति के सभी माध्यमों पर अपना नियंत्रण चाहते हैं। वे अपने समूह में किसी बाहरी को प्रवेश नहीं करने देना चाहते हैं।

इस गैंग के जैसा ही एक गैंग भारत के पारिवारिक नियंत्रण वाले कारोबारों में भी मौजूद है। इस समूह के कुछ सदस्य पिछले कुछ समय से बचने के लिए भाग रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से प्रवर्तक हैं, जिनका मानना है कि उन्हें अपनी कंपनियों पर नियंत्रण का अधिकार मिला हुआ है, जबकि उनका ज्यादा कुछ दांव पर नहीं लगा हुआ है। उनका मानना है कि वे अपनी कंपनियों में दीर्घावधि मूल्य सृजन के सबसे बेहतर संरक्षक हैं। कुछ ने बाहरी पेशेवरों को मुख्य कार्याधिकारी बनाया है, लेकिन वे मरने तक इन पेशवरों को नियंत्रित करते हैं।

जेट एयरवेज के संस्थापक और पूर्व चेयरमैन नरेश गोयल का ही उदाहरण लें। कंपनी का सीईओ नियुक्त करने के बावजूद गोयल और उनकी पत्नी ने जेट को अपनी एक दुकान के रूप में चलाया, जहां उन दोनों की मंजूरी के बिना कुछ नहीं हुआ। गोयल हमेशा अहम फैसलों में शामिल होते थे और आम तौर पर सीईओ के पास सीमित कार्यकारी शक्तियां होती थीं और वे लंबे समय तक नहीं टिक पाते थे। इससे सीईओ को नियुक्त करने की प्रक्रिया महज एक मजाक बन गई थी। जेट में 11 वर्षों के दौरान आठ सीईओ बने हैं।

उदाहरण के लिए गोयल ने पेरिस एयर शो में मीडिया के सामने घोषणा की थी कि जेट 20 नए लंबे-चौड़े विमानों के ऑर्डर देगी। उन्होंने कहा कि इन विमानों को विमानन कंपनी के बेड़े में अगले 18 महीनों के दौरान शामिल किया जाएगा ताकि वैश्विक उड़ानें शुरू करने की आकांक्षाएं पूरी की जा सकें। समस्या यह थी कि जेट के बोर्ड और उसके सीईओ को इस योजना के बारे में अगली सुबह के समाचार-पत्रों से पता चला।

> ताकतवर वंशवादी अमीर किसी बाहरी को अपने समूह में प्रवेश नहीं करने देना चाहते

भारत में परिवारों द्वारा चलाई जा रही कंपनियों में गोयल जैसे कई हैं, जो अपनी कंपनियों को अपनी जागीर के रूप में चलाते हैं। वे कंपनी के बोर्ड को अपने सगे-संबंधियों से भर देते हैं और अपने तरीके से चीजों को नियंत्रित करते हैं। साफ तौर पर ज्यादातर अवसरों को गंवा देते हैं क्योंकि वे दूसरों को सुनते नहीं हैं। पश्चिमी देशों में संस्थापक एक सीईओ को हटाते हैं और दूसरे को नियुक्त करते हैं। भारतीय प्रवर्तक एक सीईओ को हटा देते हैं और खुद सीईओ की भूमिका में आ जाते हैं। इन प्रवर्तकों में से ज्यादातर खुद अपनी धारणाओं के शिकार हैं और आम तौर पर उनके जाल में फंस जाते हैं। वह उन लोगों पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, जिन्हें उन्होंने तैयार किया है।

कुछ ऐसे भी मामले हैं, जहां बाहरी सीईओ के लिए कंपनी में लंबे समय से मौजूद कर्मचारियों की मंडली मुश्किल बन जाती है। यह मंडली ऐसे किसी प्रस्ताव को नाकाम कर देती है, जो समूह के मौजूदा ढांचे में अहम बदलाव ला सकता है। शोध में भी यह पाया गया है कि बहुत से प्रवर्तक यह सोचते हैं और दूसरों को भी यह सोचने को मजबूर करते हैं कि उनका कोई विकल्प नहीं है। उनका कोई विकल्प न होने का विचार उन्हें इस विचार से भी ज्यादा आनंद देता है कि उनके जाने के बाद संगठन खत्म हो जाएगा। हालांकि आपकी प्रतिभा का इससे कोई बेहतर सबूत नहीं हो सकता कि आप कंपनी से जाने के बाद उससे दूर हो जाते हैं। कुछ प्रवर्तक कंपनी के लिए खुद को इतना जरूरी समझ लेते हैं कि वे कंपनी को छोड़ने से ही इनकार कर देते हैं। भले ही इसके लिए पूरे बोर्ड की सेवानिवृत्ति की उम्र में बार-बार बढ़ोतरी ही क्यों न करनी पड़े।

इस बात में कोई संदेह नहीं है कि 1990 के दशक के प्रारंभ से पारिवारिक स्वामित्व वाले बहुत से कारोबार गुमनामी में चले गए हैं। मैकिंजी के हाल के एक अध्ययन में कहा गया है कि भारत में पारिवारिक स्वामित्व वाले कारोबारों में से केवल 7 फीसदी ही तीसरी पीढ़ी से आगे बढ़ पाए हैं। वैश्विक कार्याधिकारी खोज कंपनी एगोन जेंडर के एक श्वेत पत्र के मुताबिक सबसे महत्त्वपूर्ण सवाल समय है। उद्यमी के लिए पहला कदम यह समझना है कि भविष्य की यात्रा के लिए एक अलग अगुआ की जरूरत है। आम तौर पर ऐसा दौर होता है, जब संगठन की प्रगति औपचारिक संगठन, प्रणाली और प्रक्रियाओं के अभाव में धीमी हो जाती है।

भारतीय कंपनियों की समस्या यह है कि प्रवर्तक पेशेवरों को उनकी भूमिका स्पष्ट किए बिना नियुक्त करते हैं। उदाहरण के लिए इस बारे में करार करना जरूरी है कि किन मामलों का फैसला परिवार लेगा और वे कौनसे मामले होंगे, जिनमें वे पेशेवर के फैसलों का समर्थन करेंगे। कंपनियों में ऐसा औपचारिक ढांचा और प्रक्रिया होनी जरूरी है जैसी आनंद महिंद्रा और हर्ष मारीवाला ने अपने यहां लागू की है। ज्यादातर प्रवर्तक प्रणाली में काफी अस्पष्टताएं छोड़ देते हैं ताकि प्रवर्तक किसी भी समय अंदर आ सकें।

यह उचित समय है कि कॉरपोरेट इंडिया का खान मार्केट गैंग भी अपनी गलती को महसूस कर उसमें सुधार करे। अगर सम्मान करना आपकी कंपनी की संस्कृति है तो असली प्रतिभाएं आपके अनुमान से पहले निकासी का बटन दबाएंगी।

कानाफूसी

कारोबार पर असर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में त्रिभाषा फॉर्मूले का प्रस्ताव रखा गया है। यह प्रस्ताव तमिलनाडु में गहन राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। द्रविड़ राजनीतिक दलों ने इसे हिंदी विरोध का आधार बना लिया है। दिलचस्प यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता एच राजा ने ट्विटर पर उन स्कूलों की एक सूची जारी की है जो द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम के नेताओं द्वारा संचालित हैं। राजा का आरोप है कि द्रमुक नेता स्टालिन की बेटी भी स्कूल चलाती हैं और ये सारे नेता त्रिभाषा फॉर्मूले के खिलाफ इसलिए एकजुट हुए हैं क्योंकि त्रिभाषा फॉर्मूला लागू होने के बाद उनके स्कूल के कारोबार पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। राजा के मुताबिक अकेले चेन्नई शहर में द्रमुक नेता और उनके परिवार कम से कम पांच स्कूल चलाते हैं। जबकि पूरे प्रदेश में इनकी तादाद एक दर्जन से अधिक है।

गठबंधन करेगा बचाव

लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने दलित नेता प्रकाश आंबेडकर की अगुआई वाले महाराष्ट्र के वंचित बहुजन आघाडी (वीबीए) पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगाया था। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस की महाराष्ट्र प्रदेश इकाई आगामी विधानसभा चुनाव के पहले वीबीए के साथ चुनावपूर्व गठबंधन करने के लिए चर्चा कर रही है। आंबेडकर देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के पोते हैं और उनकी पार्टी को हैदराबाद के नेता असद्दुदीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन का समर्थन प्राप्त है। दोनों दलों ने लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था और अच्छी खासी तादाद में वोट भी हासिल किए थे। हालांकि उन्हें प्रदेश की 48 में से एक भी लोकसभा सीट पर जीत नहीं मिल सकी थी। कांग्रेस की हताशा भी समझ में आ रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की तरह महाराष्ट्र में भी कांग्रेस नेताओं के टूटने का खतरा उत्पन्न हो गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कांग्रेस विधायकों से बात कर उन्हें भाजपा में शामिल होने का आमंत्रण दे रहे हैं।

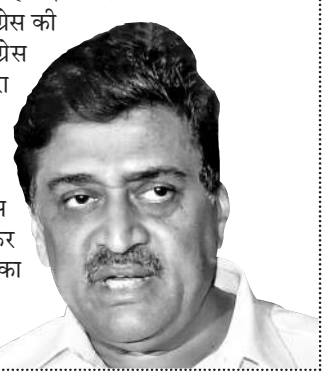

आपका पक्ष

अब 5जी सेवा का जल्द होगा आगाज

संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने मंत्रालय का कार्यभार संभालते हुए कहा कि हमारा पहला लक्ष्य 100 दिन के अंदर देश में 5जी सेवा का परीक्षण और अगले साल से इस सेवा को सक्रिय करना है। 5जी मोबाइल फोन वायरलेस सेवा की पांचवीं पीढ़ी है। पिछले जेनरेशन की तुलना में इसकी गति काफी अच्छी होगी। यह 2जी, 3जी और 4जी की पूरक होगी। भारत में इस सेवा पर काम की शुरुआत मई 2013 में हो गई थी। 5जी तकनीक के बाद इंटरनेट के उपयोगकर्ताओं को तेज गति से डेटा मिलेगा। इससे बेहतर नेटवर्क कवरेज मिलेगा और मोबाइल उपकरणों की बैटरी भी कम खर्च होगी। मोबाइल तकनीक की पहली पीढ़ी 1जी एनालॉग सेवा थी जिसे सेल्यूलर फोन के माध्यम से उपलब्ध कराया गया था। दूसरी पीढ़ी 2जी डिजिटल तकनीक पर आधारित सेवा थी जिसकी स्पेक्ट्रम क्षमता, सुरक्षा और लिखित संदेश सेवा काफी बेहतर थी। 3जी तकनीक का लक्ष्य संचार सेवाओं को तेज गति और सुरक्षा प्रदान करना था। इसके बाद 4जी तकनीक आई जो आईपी अर्थात इंटरनेट प्रोटोकोल सुविधा से लैस है और इसकी औसत संचार गति एक जीबी प्रति सेकंड है। 5जी मोबाइल संचार तकनीक इससे भी ज्यादा विकसित है। यह तेज गति वाली 5जी देश में डिजिटल क्रांति में अहम भूमिका निभाएगी जिससे भारत के सामाजिक परिवर्तन का लक्ष्य तेजी से हासिल किया जा सकेगा।

5जी मोबाइल नेटवर्क सेवा पर काम चल रहा है और संभवतः अगले साल शुरू हो जाएगा

मनीष कुमार, पटना

पृथ्वी को बचाने के लिए संकल्प

पृथ्वी को बचाने के लिए लोगों को संकल्प लेना जरूरी हो गया है। यह संकल्प बढ़ती आबादी को कम करना, अनाज और जल की बरबादी रोकना, प्लास्टिक के उपयोग में कमी लाना और पौधरोपण करना है। आज आबादी तेजी से बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी 1.2 प्रतिशत से बढ़ रही है और चीन की 0.5 प्रतिशत से बढ़ रही है। भारत की आबादी 136 करोड़ पार कर चुकी है। जनसंख्या के हिसाब से संसाधन की कमी के कारण देश में भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी आदि समस्या मौजूद है। इसलिए बढ़ती आबादी को रोकना जरूरी हो गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का स्कोर 31.1 रहा जो देश में गंभीर भुखमरी की समस्या को दर्शाता है। इसलिए लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि वे शादी, पार्टी, रेस्टारेंट में अन्न की बरबादी नहीं होने देंगे। आज जल की कमी की समस्या से जूझ रहा है। राजस्थान में 1,500 फुट गहराई में भी पानी नहीं मिल पा रहा है। प्लास्टिक पर रोक लगाना भी जरूरी हो गया है क्योंकि इसके कचरे की समस्या गहराने लगी है। प्लास्टिक का विघटन नहीं होने के कारण इसके कचरे की समस्या बढ़ती जा रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रतिदन 15,000 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। इस समस्या का उचित प्रबंध नहीं होने से गली, मोहल्ले और सड़कों पर प्लास्टिक का कचरा देखा जा सकता है। अगले 10 वर्षों में पृथ्वी का तापमान और 4 डिग्री बढ़ जाएगा। वन सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 24.39 प्रतिशत जमीन वन से घिरी है और 8 प्रतिशत वन क्षेत्र विकसित करने की जरूरत है। अतः लोगों को पौधरोपण का संकल्प लेना चाहिए।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।